Central Sector Scheme of Special Foodgrains Production Programme—Maize & Millets, with two-fold objectives of improving the productivity in areas with relatively low yields and also to attain further higher levels of production with yields above all-India average. Special efforts have also been made by delinking the price of maize from other coarse cereals and higher support price for maizeas compared to other coarse cereals.

किसानों को बोनस

*166. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :**

चौधरी हरिसिंह :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने वाले किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिए जाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस निर्णय को लागू कर दिया गया है; यदि हां, तो गेहूं की वसूली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) अभी तक इस योजना के अधीन कितना गेहूं खरीदा गया है; और

(घ) सरकार 1992-93 वर्ष के दौरान कितना गेहूं खरीदने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । मंडियों में आरम्भिक आमद उत्साहवर्द्धक रही है ।

(ग) 4-5-1992 तक 35.36 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल कर लिया गया है ।

(घ) वसूली की मात्रा पेशगी निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन केवल स्वैच्छिक आधार पर की जाती है ।

Supply of foodgrains to the Kashmir Valley

*167. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what was the quantum of foodgrains allocated to the Kashmir Valley during 1991 ;

(b) what was the quantum actually delivered against the said allocation ; and

(c) what is the shortfall, if any, alongwith the reasons therfor and also the remedial measure taken to ensure that the supply of foodgrains to Kasrmir remains available?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) to (c) The allotment/offtake of rice and wheat in respect of Kashmir Valley 1991 is given below :—

(Lakh tonnes)

Allotment		Offtake	
Rice	Wheat	Rice	Wheat
3.79	0.88	2.04	0.40

The shortfall in offtake is mainly due to operational problems because of local conditions. There is normally no problem in sending foodgrains upto Jammu. Availability of trucks for onward despatch to the Valley sometimes poses problems. FCI is making special efforts, including constant liaison with the state government to ensure despatch of adequate quantity of foodgrains to the Valley.

किराया नियंत्रण के लिये आदर्श विधान

*168. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में देश के लगभग सभी राज्यों के

मध्य तथा निम्न आय वर्गों के लोग किराये पर रहते हैं और उनका आमदनी का एक बड़ा भाग किराए के रूप में चला जाता है ,

(ख) क्या सरकार दिल्ली में किराया नियंत्रण के लिए कोई आदर्श विधान बनाने पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) आवास पर 1991 की जनगणना के आंकड़े की तारीख में उपलब्ध नहीं है । तथापि 1981 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में किराया आवास में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 49 प्रतिशत था । राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन के 44वें दौरे सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली में सेम्पल परिवारों द्वारा दिया गया औसत मासिक किराया रुपये 336.80 था ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित आदर्श किराया नियंत्रण विधेयक के आधार पर दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन विवेचनाधीन है ।

*169 [Transferred to the 13th May, 1992]

रूस में भारतीय छात्रों को अतिरिक्त राज-सहायता का दिया जाना

@*169-क. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सोवियत रूस में इस समय पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अतिरिक्त राज-सहायता दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूववर्ती सोवियत संघ में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था आरम्भ किए जाने के परिणाम स्वरूप निर्वाह लागत के बढ़ जाने के कारण भारतीय छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इस अभ्यावेदन में की गई मांग कब तक स्वीकार कर ली जाएगी, और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है कि सोवियत रूस में भारतीय छात्रों के अध्ययन में बाधा न आये ।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मास्को स्थित भारतीय दूतावास की सिफारिश पर भूतपूर्व सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे उन भारतीय छात्रों को जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भेजा जा चुका था, दुर्लभ मुद्रा में 500 रुपये प्रति मास का भत्ता संस्वीकृत किया । यह 1992 की प्रथम तिमाही के लिए एक अस्थायी उपाय था मास्को स्थित भारतीय दूतावास के इस भत्ते को जारी रखने और उसे बढ़ाने की सिफारिश की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) विदेश मंत्रालय स्वतन्त्र राज्यों के राजमंडल और इसके सदस्य गणराज्यों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर डालने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय छात्रों के संबंध में भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा कि कई सभी वचनबद्धताओं का सम्मान किया जाए । सरकार ने उन छात्रों के माता-पिता को कुछ विनियम सुविधाओं को भी अनुमति प्रदान की है जो स्वयं अपनी और से अथवा कुछ प्राईवेट एजेंसियों के माध्यम से गए हैं ।

Publication of Dr. Ambedkar's works

*170. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether any proposal has been considered by Government to publish

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 190, 11 मई, 1992 से स्थानान्तरित ।

@Previously Starred Question 7 , transferred from the 30th April, 1992.